



# Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC  
| SSC | BANK RAILWAY Exam

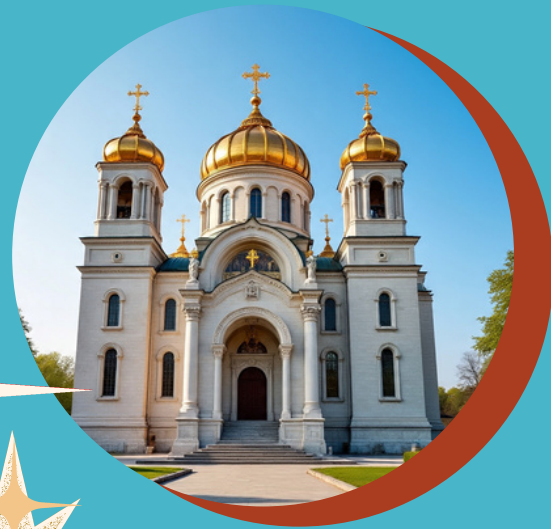


## BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

12 - 18 OCTOBER

3RD WEEK OF OCTOBER

50+ MCQ  
with detailed  
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



**Ques: From which date will State and Central Co-operative Banks come under the ambit of the RBI's Integrated Ombudsman Scheme, 2021?**

**राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक किस तारीख से RBI की एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के दायरे में आएंगे?**

- A. August 15, 2025
- B. October 1, 2025
- C. November 1, 2025
- D. December 31, 2025
- E. January 1, 2026

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI), under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, has issued a notification to include State and Central Co-operative Banks under the Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अधिसूचना जारी कर राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के दायरे में शामिल किया है।
- This inclusion will be effective from November 1, 2025, expanding the scheme to cover Commercial Banks, RRBs, Co-operative Banks, NBFCs (excluding HFCs) with certain asset thresholds, and Credit Information Companies.
- यह विस्तार योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, तय संपत्ति आकार वाली गैर) बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-HFC को छोड़कर, और क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी शामिल करता है।
- RB-IOS provides a fast, cost-effective, and transparent grievance redressal mechanism for customers of regulated entities.
- RB-IOS ग्राहकों को तेज़, किफायती और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करती है।

---

**Ques: Who has been appointed as Administrator of Irinjalakuda Town Co-operative Bank after RBI superseded its board?**

**आरबीआई द्वारा इरिंजालकुडा टाउन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग करने के बाद -**

**प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?**

- A. Mohanan K / मोहनन के
- B. T.A. Mohamed Sageer / टीमोहम्मद सगीर .ए.
- C. Raju S. Nair / राजू एसनायर .
- D. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E. V. Vaidyanathan / वीवैद्यनाथन .

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI), under Section 36AAA read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, superseded the board of Irinjalakuda Town Co-operative Bank Ltd. for 12 months due to poor financial condition and governance issues.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक कमियों के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AAA और धारा 56 के तहत इरिंजालकुडा टाउन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड को-12 महीनों के लिए भंग कर दिया।
- Shri Raju S. Nair, former Vice President of Federal Bank, has been appointed as Administrator to manage the bank's affairs during this period.
- इस अवधि के दौरान बैंक के कार्यों के प्रबंधन के लिए फेडरल बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजू एसयर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
- A Committee of Advisors, including Shri Mohanan K and Shri T.A. Mohamed Sageer, has also been formed to assist the Administrator.
- प्रशासक को उनके कर्तव्यों में सहायता करने के लिए श्री मोहनन के और श्री टी .ए. गीर सहित एक सलाहकार समिति भी गठित की गई है।मोहम्मद स

---

**Ques: Who launched the pilot linking the FX-Retail platform of Clearcorp with the Bharat Bill Payment System (Bharat Connect)?**

**किसने Clearcorp के FX-Retail प्लेटफॉर्म को Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) से जोड़ने वाला पायलट लॉन्च किया?**

- A. T. Rabi Sankar / टीरबी शंकर .
- B. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास

- C. Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण  
D. Ajay Tyagi / अजय त्यागी  
E. Rajeev Kumar / राजीव कुमार

**Answer: Option A**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- RBI Deputy Governor T. Rabi Sankar launched a pilot linking the FX-Retail platform of Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. with the Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) at the Global Fintech Fest (GFF) 2025 in Mumbai.
  - RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने मुंबई में .Global Fintech Fest (GFF) 2025 में Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. के FX-Retail प्लेटफॉर्म को Bharat Bill Payment System (Bharat Connect) से जोड़ने वाला पायलट लॉन्च किया।
  - The linkage allows customers of Axis Bank, Federal Bank, ICICI Bank, SBI, and Yes Bank to transact on the FX-Retail platform via bank digital channels or Third Party Application Providers (TPAPs).
  - इस लिंक से Axis Bank, Federal Bank, ICICI Bank, SBI और Yes Bank के ग्राहक बैंक डिजिटल चैनलों या थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स (TPAPs) के माध्यम से FX-Retail प्लेटफॉर्म पर लेनदेन कर सकते हैं।-
  - Customers can access FX-Retail through CRED and Mobikwik applications to purchase US Dollars against Indian Rupees on a 'value cash' basis.
  - ग्राहक CRED और Mobikwik एप्लिकेशन के माध्यम से FX-Retail का उपयोग करके भारतीय रुपये के बदले अमेरिकी डॉलर 'वैल्यू कैश' आधार पर खरीद सकते हैं।
- 

**Ques: What is the initial transaction limit for UPI biometric authentication introduced by the Government of India?**

**सरकार द्वारा शुरू किए गए UPI बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए प्रारंभिक लेनदेन सीमा क्या है?**

- A. ₹1,000  
B. ₹2,500  
C. ₹5,000  
D. ₹10,000  
E. ₹15,000

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Government of India has introduced on-device biometric authentication for UPI payments using face or fingerprint verification, announced by DFS Secretary M. Nagaraju at the Global Fintech Fest.
- भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को तेज़, सुरक्षित और PIN-रहित बनाने के लिए चेहरे और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण आधारित UPI लेनदेन शुरू किया है, जिसकी घोषणा वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एमनागराजु ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में की।
- Initially, such biometric transactions will be capped at ₹5,000, and the limit will be reviewed later.
- शुरुआत में ऐसे बायोमेट्रिक ट्रांज़ैक्शन की सीमा ₹5,000 रखी गई है, जिसे बाद में पुनः समीक्षा किया जाएगा।
- Aadhaar-based facial authentication also allows secure setting or resetting of the UPI PIN, while NPCI mandates disabling the feature on device changes or PIN reset and marking users inactive if no transaction occurs within 90 days.
- आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से उपयोगकर्ता अपने UPI PIN को सुरक्षित रूप से सेट या रीसेट कर सकते हैं, और NPCI ने निर्देश दिया है कि डिवाइस बदलने या PIN रीसेट होने पर फीचर को डिसेबल किया जाए तथा 90 दिनों तक कोई ट्रांज़ैक्शन न होने पर उपयोगकर्ता को निष्क्रिय माना जाए।

---

**Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a monetary penalty of ₹31.80 lakh on which bank for non-compliance with its directions under the Credit Card and Debit Card - Issuance and Conduct Directions, 2022?**

**RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण दिशानिर्देश-, 2022 के तहत दिशा निर्देशों का पालन न करने पर-₹31.80 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है?**

- A. Citibank N.A. / सिटीबैंक एन.ए.
- B. HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- C. American Express Banking Corp. / अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.
- D. Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- E. Deutsche Bank / डॉयचे बैंक

**Answer: Option C**

---

### Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹31.80 lakh on American Express Banking Corp. for non-compliance with its Credit Card and Debit Card - Issuance and Conduct Directions, 2022.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण दिशा-निर्देश, 2022 का पालन नहीं किया।
- The penalty was imposed under Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) के साथ धारा 46(4)(i) के तहत लगाया गया।
- The penalty followed the findings of Inspection for Supervisory Evaluation (ISE 2024), which revealed lapses in reversing credit balances for certain cardholders arising from refunds, failed, or reversed transactions.
- यह जुर्माना ISE 2024 निरीक्षण के निष्कर्षों के बाद लगाया गया, जिसमें रिफंड, असफल या रिवर्स लेनदेन से उत्पन्न कुछ कार्डधारकों के क्रेडिट बैलेंस को वापस न करने की कमियाँ पाई गईं।
- RBI clarified that the action targets regulatory compliance deficiencies and does not affect the validity of any transactions or agreements between the bank and its customers.
- RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन की कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी लेनदेन या समझौते की वैधता - को प्रभावित करना नहीं है।

---

**Ques: Which Indian payments system has been announced as the first partner onboarded on PayPal World, PayPal's global payments platform?  
किस भारतीय भुगतान प्रणाली को PayPal World, PayPal के वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पर पहले पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है?**

- A. BharatQR / भारतQR
- B. UPI / यूपीआई
- C. Paytm / पेटीएम

- D. Google Pay / गूगल पे  
E. PhonePe / फोनपे

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- PayPal CEO Alex Chriss announced that India's Unified Payments Interface (UPI) is the first payments-system partner to be onboarded on PayPal World, the newly launched global payments platform.
  - PayPal के CEO एलेक्स क्रिस ने घोषणा की कि भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को PayPal World, नए लॉन्च किए गए वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पर पहला भुगतान प्रणाली पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है।
  - PayPal World enables cross-border transactions by allowing users to use local payment systems and digital wallets for international commerce.
  - PayPal World सीमापार लेनदेन को सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थानीय भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।
  - Other partner wallets already associated with PayPal World include Mercado Pago (Latin America), Tenpay Global (China), and Venmo (USA).
  - PayPal World से पहले जुड़े अन्य पार्टनर वॉलेट्स में Mercado Pago (लैटिन अमेरिका), Tenpay Global (चीन), और Venmo (यूएसए) शामिल हैं। (
- 

**Ques: Which company recently rebranded its insurance businesses as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance after acquiring full ownership?  
किस कंपनी ने हाल ही में अपनी बीमा कंपनियों का नाम बदलकर Bajaj General Insurance और Bajaj Life Insurance रखा, पूर्ण स्वामित्व हासिल करने के बाद?**

- A. ICICI Lombard / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड  
B. HDFC ERGO / एचडीएफसी एर्गो  
C. Tata AIG / टाटा एआईजी  
D. SBI General Insurance / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस  
E. Bajaj Finserv / बजाज फिनसर्व

**Answer: Option E**

---

### Explanation / व्याख्या:

- Bajaj Finserv Limited has rebranded its insurance businesses as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance, dropping the Allianz branding.
- बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने अपनी बीमा कंपनियों का नाम बदलकर Bajaj General Insurance और Bajaj Life Insurance रखा, और Allianz ब्रांडिंग हटा दी।
- Earlier in 2025, Bajaj Finserv acquired Allianz SE's 26% stake in its two insurance joint ventures for ₹24,180 crore, gaining full ownership.
- इस वर्ष के शुरू में, बजाज फिनसर्व ने अपनी दो बीमा जॉइंट वेंचर में Allianz SE के 26% शेयर ₹24,180 करोड़ में खरीदे, और पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया।
- The rebranding campaign is supported by the tagline: "100% Bajaj. Made in India. Made for India. Made by India."
- इस रिब्रांडिंग अभियान का समर्थन टैगलाइन के साथ किया गया है : "100% Bajaj. Made in India. Made for India. Made by India."

---

**Ques: What is the purpose of RBI's proposed Expected Credit Loss (ECL) framework?**

**RBI द्वारा प्रस्तावित ECL ढांचे का उद्देश्य क्या है?**

- A. To reduce CRR and SLR for banks / बैंकों के लिए CRR और SLR कम करना
- B. To replace the RTGS payment system / RTGS भुगतान प्रणाली को बदलना
- C. To align India's banking norms with global standards and improve credit risk assessment / भारत के बैंकिंग मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप करना और क्रेडिट जोखिम आकलन में सुधार करना
- D. To promote digital payment systems / डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना
- E. To merge all public sector banks into one / सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना

**Answer: Option C**

---

### Explanation / व्याख्या:

- The RBI's proposed Expected Credit Loss (ECL) framework aims to align Indian banking regulations with international accounting and risk management

standards.

- RBI द्वारा प्रस्तावित अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ECL) ढांचा भारतीय बैंकिंग नियमों को अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और जोखिम प्रबंधन मानकों के अनुरूप बनाने का उद्देश्य रखता है।
- It replaces the incurred-loss model, requiring banks to classify loans based on credit risk and set aside provisions for potential losses in advance.
- यह पुराने 'incurred-loss' मॉडल की जगह लेता है, बैंकों को ऋणों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करने और संभावित नुकसान के लिए अग्रिम प्रावधान अलग रखने की आवश्यकता होती है।
- The framework will come into effect from April 1, 2027, enhancing the banking system's stability and transparency.
- यह ढांचा 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

---

**Ques: Which Urban Cooperative Bank's licence has been cancelled by the Reserve Bank of India (RBI) in October 2025?**

**अक्टूबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस - रद्द कर दिया है?**

- A. Jijamata Sahakari Bank, Satara / जीजामाता सहकारी बैंक, सतारा
- B. Saraswat Co-operative Bank, Mumbai / सारस्वत सहकारी बैंक, मुंबई
- C. Rupee Co-operative Bank, Pune / रुपया सहकारी बैंक, पुणे
- D. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank, Mumbai / पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक, मुंबई
- E. Abhyudaya Co-operative Bank, Mumbai / अभ्युदय सहकारी बैंक, मुंबई

**Answer: Option A**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Jijamata Sahakari Bank, an Urban Cooperative Bank (UCB) based in Satara, Maharashtra.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिजामाता सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
- The licence was cancelled due to the bank's poor financial condition and

failure to comply with the regulatory norms under the Banking Regulation Act, 1949.

- यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत नियामक मानकों का पालन न करने के कारण की गई है।
- Following the cancellation, the bank has been barred from conducting any banking business effective from the close of business on October 7, 2025.
- लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक को 7 अक्टूबर 2025 से किसी भी बैंकिंग गतिविधि को संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Notably, the bank's licence was earlier cancelled in 2016 but later restored in 2019 after an appeal made by the bank.
- उल्लेखनीय है कि इस बैंक का लाइसेंस पहले 2016 में रद्द किया गया था, जिसे 2019 में बैंक की अपील पर बहाल कर दिया गया था।

---

**Ques: Which initiative has the Reserve Bank of India (RBI) launched to allow fintech companies to develop and test use cases under the e-Rupee pilot?**

**रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने किस पहल को शुरू किया है ताकि फिनटेक कंपनियाँ ई-रुपया पायलट के तहत उपयोग के मामलों और समाधान विकसित और परीक्षण कर सकें?**

- A. Digital Rupee Sandbox / डिजिटल रुपया सैंडबॉक्स
- B. Fintech Innovation Hub / फिनटेक इनोवेशन हब
- C. E-Payments Pilot Program / ईभुगतान पायलट प्रोग्राम-
- D. Retail Banking Sandbox / रिटेल बैंकिंग सैंडबॉक्स
- E. Digital Finance Lab / डिजिटल फाइनेंस लैब

**Answer: Option A**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has launched a retail sandbox for its Central Bank Digital Currency (CBDC) to allow fintech companies to develop and test use cases under the ongoing e-Rupee pilot.
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, ताकि फिनटेक कंपनियाँ चल रहे ईरुपया पायलट के तहत - क्षण कर सकें। उपयोग के मामलों और समाधान विकसित और परी
- The e-Rupee retail pilot, first launched on December 1, 2022, now provides a

platform for innovative product deployment.

- दिसंबर 1, 2022 को शुरू हुए ईरुपया रिटेल पायलट के तहत अब नवाचारी उत्पादों को - कंपनियों को मिलेगा। विकसित और लागू करने का अवसर फिनटेक
- The initiative is led by Suvendu Pati.
- इस पहल का नेतृत्व सुवेंदु पाटी कर रहे हैं।

---

**Ques: The Reserve Bank of India has launched the 71st round of which quarterly survey for the reference period July – September 2025?**

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई – सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए किस तिमाही सर्वेक्षण का 71वां चरण शुरू किया है?**

- A. Industrial Outlook Survey (IOS) / औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण
- B. Consumer Confidence Survey (CCS) / उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
- C. Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey (OBICUS) / ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
- D. Inflation Expectations Survey (IES) / मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण
- E. Services Sector Utilisation Survey / सेवा क्षेत्र उपयोग सर्वेक्षण

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The RBI launched the 71st round of its Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey (OBICUS) for July–September 2025 (Q2: 2025-26).
- RBI ने जुलाई–सितंबर 2025 (Q2: 2025-26) की अवधि के लिए ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (OBICUS) का 71वां चरण शुरू किया है।
- This survey, conducted quarterly since 2008, tracks manufacturing sector performance in terms of new orders, inventories, production levels, and capacity utilisation.
- यह सर्वेक्षण 2008 से तिमाही आधार पर किया जा रहा है ताकि विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों को समझा जा सके।
- Data collected helps the RBI in monetary policy formulation, while company-level data remains confidential and is not publicly disclosed.
- एकत्र किए गए डेटा से RBI को मौद्रिक नीति निर्माण में मदद मिलती है, और कंपनी स्तर के डेटा को गोपनीय रखा जाता है तथा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता।

**Ques: RBI imposed a monetary penalty of ₹4.20 lakh on which NBFC for non-compliance with KYC Directions, 2016?**

**आरबीआई ने KYC निर्देश, 2016 के अनुपालन में विफल रहने पर किस एनबीएफसी पर ₹4.20 लाख का जुर्माना लगाया?**

- A. Bajaj Finance Ltd / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
- B. HDB Financial Services Ltd / एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- C. Tata Capital Financial Services / टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज
- D. Muthoot Finance / मुथूट फाइनेंस
- E. Shriram Finance / श्रीराम फाइनेंस

**Answer: Option B**

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI), exercising powers under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the RBI Act, 1934, imposed a monetary penalty of ₹4.20 lakh on HDB Financial Services Ltd for non-compliance with certain provisions of the KYC Directions, 2016.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और धारा 58B(5)(aa) के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर KYC निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹4.20 लाख का जुर्माना लगाया।
- The penalty follows a statutory inspection referencing the company's financial position as on March 31, 2024, which revealed deficiencies in obtaining PAN/Form 60 in certain loan accounts for FY 2023–24.
- यह जुर्माना कंपनी की 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया, जिसमें FY 2023–24 के कुछ ऋण खातों में PAN/फॉर्म 60 प्राप्त करने में कमियां पाई गईं।
- RBI clarified that this action targets regulatory compliance lapses and does not question the validity of any transactions undertaken by the company.
- RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा किए गए किसी लेनदेन की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।-

**Ques: Which organization launched its 2nd verified WhatsApp channel for public awareness under the 'RBI Kehta Hai' initiative?**

**'RBI कहता है' पहल के तहत जन जागरूकता के लिए दूसरा सत्यापित-व्हाट्सएप चैनल किस संगठन ने शुरू किया है?**

- A. SEBI / सेबी
- B. IRDAI / आईआरडीएआई
- C. RBI / आरबीआई
- D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E. NABARD / NABARD

**Answer: Option C**

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) launched its second verified WhatsApp channel in October 2025 under its 'RBI Kehta Hai' initiative.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2025 में अपनी 'RBI कहता है' पहल के तहत दूसरा सत्यापित व्हाट्सएप चैनल शुरू किया।
- The initiative aims to make financial information easily accessible to the public in a simple, direct, and effective manner, thereby enhancing trust and financial literacy.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय जानकारी को सरल, सीधा और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचाना है, जिससे विश्वास और वित्तीय साक्षरता बढ़े।
- The first verified WhatsApp number (+91 99990 41935) was launched in April 2025, and the second verified number (+91 99309 91935) has now been added.
- पहला सत्यापित व्हाट्सएप नंबर (+91 99990 41935) अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था, और अब दूसरा नंबर (+91 99309 91935) जोड़ा गया है।
- Citizens can now receive official updates, alerts, and public awareness messages directly from RBI on WhatsApp.
- अब नागरिक व्हाट्सएप पर RBI से सीधे आधिकारिक अपडेट, अलर्ट और जनजागरूकता - कर सकते हैं। संदेश प्राप्त
- RBI has advised users to follow only verified accounts with the blue tick to avoid fraud.
- RBI ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे केवल ब्लू टिक वाले सत्यापित खातों को ही फॉलो करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।

**Ques: As per the latest amendment to the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, how much will vehicles be charged if they pay toll fees via UPI without a valid FASTag?**

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दर निर्धारण और संग्रह), 2008 में हालिया संशोधन के अनुसार, यदि वाहन वैध फास्टैग के बिना यूपीआई के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान करते हैं, तो उनसे कितना शुल्क लिया जाएगा?

- A. Equal to applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क के बराबर
- B. 1.25 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 1.25 गुना
- C. 1.5 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 1.5 गुना
- D. 2 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 2 गुना
- E. 3 times the applicable user fee / लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 3 गुना

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Government of India has amended the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दर निर्धारण और संग्रह), 2008 में संशोधन किया है।
- As per the new rule, vehicles entering a fee plaza without a valid, functional FASTag will be charged **twice** the applicable user fee if payment is made in cash.
- नए नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन वैध फास्टैग के बिना नकद भुगतान करता है, तो उससे लागू शुल्क का **दोगुना** लिया जाएगा।
- However, such users opting to pay the fee via Unified Payment Interface (UPI) will be charged **1.25 times** the applicable user fee for that category of vehicle.
- जबकि ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान करते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क का **1.25 गुना** लिया जाएगा।
- For example, if a vehicle needs to pay ₹100 via valid FASTag, the fee will be ₹200 if paid in cash and ₹125 if paid via UPI.
- उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग से ₹100 का भुगतान करना है, तो नकद भुगतान करने पर ₹200 और यूपीआई से भुगतान करने पर ₹125 देना होगा।
- This amendment aims to strengthen the fee collection process, enhance transparency in toll collection, and promote ease of commuting for National

Highway users.

- यह संशोधन शुल्क संग्रह प्रक्रिया को मजबूत करने, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है।
- The notification will come into effect from November 15, 2025.
- यह अधिसूचना 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।

---

**Ques: Which bank in India has become the first to act as a UPI-ICD Acquirer, allowing UPI-based interoperable cash deposits?**

**भारत में कौन सा बैंक पहला बन गया है जो UPI-ICD Acquirer के रूप में कार्य करेगा, और UPI-आधारित इंटरऑपरेबल नकद जमा स्वीकार करेगा?**

- A. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B. Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- C. TJSB Sahakari Bank / टीजेएसबी सहकारी बैंक
- D. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- TJSB Sahakari Bank has gone live as the first bank in India to act as a UPI-ICD Acquirer, meaning it can accept UPI-based interoperable cash deposits.
- टीजेएसबी सहकारी बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जो UPI-ICD Acquirer के रूप में कार्य करेगा, यानी यह UPI-आधारित इंटरऑपरेबल नकद जमा स्वीकार कर सकता है।
- The rollout uses TJSB's **Android Cash Recycler Machine (CRM)**, which accepts cash deposits via a UPI QR code and may recycle cash for withdrawals.
- यह सुविधा टीजेएसबी की **एंड्रॉइड कैश रीसायकलर मशीन (CRM)** के माध्यम से उपलब्ध है, जो UPI QR कोड से नकद जमा स्वीकार करती है और निकासी के लिए नकद पुनः उपयोग कर सकती है।

**How it works (in simple terms):**

- Go to any bank's cash deposit machine (CDM) supporting UPI-ICD.
- Select the **UPI-ICD option**.

- Enter your **UPI ID**.
- Machine shows your bank name and account details.
- Insert cash → amount credited instantly via UPI rails.
- Receive a **UPI transaction receipt**, similar to any UPI payment.

सरल शब्दों में काम करने का तरीका:

- किसी भी बैंक की UPI-ICD समर्थित नकद जमा मशीन पर जाएँ।
  - **UPI-ICD** विकल्प चुनें।
  - अपना **UPI ID** दर्ज करें।
  - मशीन आपके बैंक का नाम और खाता विवरण दिखाएगी।
  - नकद डालें → राशि तुरंत UPI के माध्यम से आपके खाते में जमा हो जाएगी।
  - आपको **UPI लेनदेन रसीद** प्राप्त होगी, जैसे किसी भी UPI भुगतान में मिलती है।
- 
- As per NPCI circular, the limit is **up to ₹50,000 per transaction**.
  - NPCI सर्कुलर के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन की सीमा **₹50,000** तक है।
  - Union Bank of India had earlier introduced a **pilot UPI-ICD product** in cash recycler machines.
  - इससे पहले, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नकद रीसायकलर मशीनों में **पायलट UPI-ICD** उत्पाद शुरू किया था।

---

**Ques: What is the maximum withdrawal limit imposed by RBI on The Baghat Urban Co-operative Bank Ltd., Solan?**

आरबीआई द्वारा द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड-, सोलन पर अधिकतम निकासी सीमा कितनी तय की गई है?

- A. ₹5,000
- B. ₹10,000
- C. ₹25,000
- D. ₹50,000
- E. ₹1,00,000

**Answer: Option B**

---

### Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has imposed several restrictions on The Baghat Urban Co-operative Bank Ltd., Solan under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, effective from October 8, 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड-, सोलन पर 8 अक्टूबर 2025 से कई प्रतिबंध लगाए हैं।
- As per RBI's directive, depositors are allowed to withdraw **up to ₹10,000** only from the total balance held in all their accounts (savings or current) with the bank.
- RBI के निर्देशानुसार, जमाकर्ताओं को अपने सभी खातों वलसे के (बचत या चालू) **₹10,000 तक** निकासी की अनुमति है।
- These restrictions have been imposed due to the bank's poor liquidity position and to protect the interest of depositors.
- ये प्रतिबंध बैंक की कमजोर तरलता स्थिति और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
- Eligible depositors can claim up to ₹5,00,000 from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) as per the DICGC Act, 1961.
- योग्य जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के अनुसार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि पर **₹5,00,000 तक** का दावा कर सकते हैं।

---

**Ques: The recently launched Foreign Currency Settlement System (FCSS) at GIFT City currently supports transactions in which currency?**

हाल ही में गिफ्ट सिटी में शुरू की गई विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) वर्तमान में किस मुद्रा में लेनदेन का समर्थन करती है?

- A. Euro / यूरो
- B. Pound / पाउंड
- C. US Dollar / अमेरिकी डॉलर
- D. Yen / येन
- E. Rupee / रुपया

**Answer: Option C**

---

### Explanation / व्याख्या:

- The Foreign Currency Settlement System (FCSS), launched at GIFT City during the Global Fintech Fest 2025, currently supports only US dollar transactions with Standard Chartered Bank as the settlement partner.
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान शुरू की गई विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) फिलहाल केवल अमेरिकी डॉलर लेनदेन का समर्थन करती है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक निपटान भागीदार है।
- The system enables near real-time settlements without traditional banking intermediaries, currently limited to IFSC Banking Units (IBUs) within GIFT City, Gujarat.
- यह प्रणाली पारंपरिक बैंकिंग माध्यमों के बिना लगभग वास्तविक समय में लेनदेन का निपटान सक्षम बनाती है और फिलहाल गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (IBUs) तक सीमित है।
- The upcoming expansion will include Euro and British Pound to make GIFT City a global currency settlement hub.
- आगामी विस्तार में यूरो और ब्रिटिश पाउंड को शामिल किया जाएगा ताकि गिफ्ट सिटी को वैश्विक मुद्रा निपटान केंद्र बनाया जा सके।

---

**Ques: Which organization has launched its new tech subsidiary 'NPCI Tech Solutions Limited (NTSL)' to promote innovation and research in the fintech sector?**

**किस संगठन ने फिनटेक क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई तकनीकी सहायक कंपनी 'एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL)' लॉन्च की है?**

- A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B. SIDBI / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- C. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D. NITI Aayog / नीति आयोग
- E. National Payments Corporation of India / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

**Answer: Option E**

---

## Explanation / व्याख्या:

- National Payments Corporation of India (NPCI) launched its new tech subsidiary 'NPCI Tech Solutions Limited (NTSL)' aimed at promoting experimentation and breakthrough innovations in the financial technology (fintech) sector.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में (फिनटेक) प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी नई तकनीकी सहायक कंपनी 'एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL)' शुरू की है।
- The announcement was made at the Global Fintech Fest 2025 held in Mumbai.
- इसकी घोषणा मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान की गई।
- The subsidiary will focus on innovation, research, and development in areas such as AI-based fraud detection, real-time payments infrastructure, and cross-border payment systems.
- यह सहायक कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोखाधड़ी पहचान, रियलटाइम - पार भुगतान प्रणालियों जैसे क्षेत्र-भुगतान अवसंरचना और सीमाओं में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होगी।
- With this, NTSL joins the list of existing subsidiaries of NPCI — NPCI BHIM Services Limited (NBSL), NPCI International Payments Limited (NIPL), and NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL).
- इसके साथ ही, NTSL अब NPCI की मौजूदा सहायक कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है — एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL)।
- NTSL commenced operations with an authorized capital of Rs. 1.00 million and a paid-up capital of Rs. 0.50 million.
- NTSL ने 1.00 मिलियन रुपये की अधिकृत पूंजी और 0.50 मिलियन रुपये की चुकता पूंजी के साथ अपना संचालन शुरू किया।
- Key Directors include Ajay Kumar Choudhary, Dilip Asbe Pratap, Krishnamurthy Viswanath, and Nitin Mishra.
- इसके प्रमुख निदेशकों में अजय कुमार चौधरी, दिलीप अस्बे प्रताप, कृष्णमूर्ति विश्वनाथ और नितिन मिश्रा शामिल हैं।

**Ques: What is the rate of interest on the Government of India Floating Rate Bond 2028 (GOI FRB 2028) for the period October 4, 2025 – April 3, 2026?**

**भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 (GOI FRB 2028) पर 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए ब्याज दर क्या है?**

- A. 6.10%
- B. 6.22%
- C. 6.35%
- D. 6.50%
- E. 6.75%

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) announced that the rate of interest on the Government of India Floating Rate Bond (FRB) 2028 for the half-year period from October 4, 2025 to April 3, 2026 will be 6.22% per annum.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 पर 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 तक की छमाही अवधि के लिए 6.22% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।
- The FRB 2028 carries a floating coupon rate, which changes periodically based on the Weighted Average Yield (WAY) of 182-day Treasury Bills (T-Bills).
- FRB 2028 पर फ्लोटिंग कूपन दर लागू होती है, जो 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) की भारित औसत प्रतिफल दर (WAY) पर आधारित है।
- The base rate for FRB 2028 is equivalent to the average of the last three T-Bill auctions, plus a fixed spread of 0.64%.
- FRB 2028 की आधार दर पिछली तीन T-Bill नीलामियों के औसत के बराबर होती है, जिसमें 0.64% का निश्चित स्प्रेड जोड़ा जाता है।
- The rate revision is done every six months based on the latest T-Bill yields to ensure market-linked returns.
- यह दर हर छह महीने में नवीनतम T-Bill प्रतिफल के आधार पर संशोधित की जाती है ताकि बाजार से जुड़ा रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके।
- This announcement was made by Ajit Prasad, Deputy General Manager (Communications), RBI, on October 3, 2025.
- यह घोषणा अजीत प्रसाद, उप महाप्रबंधक(संचार), RBI द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को की गई।

**Ques: Which bank has officially launched Innovation Banking in India with a USD 1 billion non-dilutive debt capital allocation for startups?**

**किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की गैर-घटती ऋण पूंजी आवंटन के साथ 'इनोवेशन बैंकिंग' आधिकारिक रूप से शुरू की है?**

- A. HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- B. Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- C. Citibank / सिटीबैंक
- D. DBS Bank / डीबीएस बैंक
- E. Barclays Bank / बार्कलेज बैंक

**Answer: Option A**

**Explanation / व्याख्या:**

- HSBC has officially launched Innovation Banking in India — a focused proposition tailored for the startup and venture ecosystem.
- एचएसबीसी ने भारत में इनोवेशन बैंकिंग आधिकारिक रूप से शुरू की है — जो स्टार्टअप और वेंचर इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से तैयार पहल है।
- The bank will allocate USD 1 billion in non-dilutive debt capital for Indian startups. “Non-dilutive” means this is lending (debt), not equity — so startups can scale without giving away ownership.
- बैंक भारतीय स्टार्टअप्स के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की गैरघटती ऋण पूंजी - आवंटित करेगा। “गैरघटती-” का अर्थ है कि यह ऋण है, इक्विटी नहीं — यानी स्टार्टअप्स को अपनी हिस्सेदारी बेचे बिना विस्तार करने की सुविधा मिलेगी।
- The initiative will support companies from early- to late-stage growth, up to IPO.
- यह पहल कंपनियों को प्रारंभिक से लेकर आईपीओ तक के विकास चरणों में सहायता प्रदान करेगी।
- The India team is led by Dilip Gopinath, Head of HSBC Innovation Banking India.
- भारत में इस पहल का नेतृत्व दिलीप गोपीनाथ, प्रमुख, एचएसबीसी इनोवेशन बैंकिंग इंडिया, कर रहे हैं।
- Earlier, HSBC had committed USD 600 million in lending support for tech-led high-growth startups in India, up from USD 250 million earlier.
- इससे पहले, एचएसबीसी ने भारत में प्रौद्योगिकीआधारित तेजी से बढ़ते स्टार-टअप्स के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता का वादा किया था, जो पहले 250

मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाई गई थी।

**About HSBC :**

- Established : 1865
- HQ : London, England, United Kingdom
- CEO : Georges Elhedery

---

**Ques: What is the new minimum threshold for block deals as per SEBI's latest revision?**

सेबी के हालिया संशोधन के अनुसार ब्लॉक डील की नई न्यूनतम सीमा क्या है?

- A. ₹5 crore
- B. ₹10 crore
- C. ₹15 crore
- D. ₹25 crore
- E. ₹50 crore

**Answer: Option D**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) raised the minimum block deal limit from ₹10 crore to ₹25 crore to enhance market liquidity and transparency.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ब्लॉक डील की न्यूनतम सीमा ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹25 करोड़ कर दी है ताकि बाजार की तरलता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
- SEBI also expanded the **price band** for executing block trades, aiming to improve price discovery and reduce speculative trades.
- सेबी ने ब्लॉक ट्रेड्स के लिए मूल्य सीमा का विस्तार भी किया है (प्राइस बैंड), ताकि मूल्य खोज में सुधार और सट्टा व्यापार में कमी लाई जा सके।
- The step will lead to better liquidity in normal trades and smoother price movements, benefiting overall market stability.
- यह कदम सामान्य ट्रेडिंग में बेहतर तरलता और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करेगा, जिससे कुल मिलाकर बाजार की स्थिरता मजबूत होगी।

**Ques: SEBI is working with which two institutions to enable remote KYC access for NRIs?**

**SEBI किस दो संस्थाओं के साथ मिलकर एनआरआई के लिए दूरस्थ KYC सुविधा ला रहा है?**

- A. RBI and UIDAI / आरबीआई और यूआईडीएआई
- B. NPCI and RBI / एनपीसीआई और आरबीआई
- C. UIDAI and Finance Ministry / यूआईडीएआई और वित्त मंत्रालय
- D. RBI and IRDAI / आरबीआई और IRDAI
- E. None of These / इनमें से कोई नहीं

**Answer: Option A**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- SEBI is collaborating with RBI and UIDAI to allow Non-Resident Indians (NRIs) to complete KYC remotely without visiting India.
- SEBI आरबीआई और UIDAI के साथ मिलकर एनआरआई को भारत आए बिना ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से KYC पूरा करने की सुविधा देगा।
- This initiative is in the testing phase and aims to simplify investment and account opening for NRIs in Indian financial markets.
- यह पहल परीक्षण चरण में है और इसका उद्देश्य एनआरआई के लिए भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश और खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- Once launched, NRIs will be able to verify their identity and invest in India remotely, boosting their participation in the financial system.
- लॉन्च होने के बाद, एनआरआई अपनी पहचान दूरस्थ रूप से सत्यापित करके भारत में निवेश कर सकेंगे, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

---

**Ques: What new feature did NPCI unveil at the Global Fintech Festival 2025 for UPI transactions?**

**NPCI ने Global Fintech Festival 2025 में यूपीआई लेनसी नई सुविधा -देन के लिए कौन-की घोषणा की?**

- A. UPI transactions via cryptocurrency / क्रिप्टोकॉरेन्सी के माध्यम से यूपीआई लेनदेन-
- B. On-device biometric authentication, UPI Lite for smart glasses, Aadhaar-based face authentication, and Multi-Signatory UPI / डिवाइसआधारित -

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट ग्लास के लिए यूपीआई लाइट, आधारआधारित फेस - ऑथेंटिकेशन और मल्टीसिग्रेचरी यूपीआई-

C. UPI only through debit cards / केवल डेबिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई

D. UPI PIN removal for all transactions / सभी लेनदेन के लिए यूपीआई पिन हटाना-

E. QR code payments disabled / क्यूआर कोड भुगतान बंद करना

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- At the Global Fintech Festival 2025, NPCI (with support from RBI/DFS) introduced several enhancements to UPI authentication.
- Global Fintech Festival 2025 में, NPCI (RBI/DFS के सहयोग सेने यूपीआई ( ऑथेंटिकेशन में कई नईसुविधाओं की घोषणा की।
- On-device biometric authentication allows fingerprint or facial recognition for transactions up to ₹5,000, avoiding the need to enter UPI PIN.
- डिवाइसआधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के तहत-, 5,000 रुपये तक के लेनदेन में - फिंगरप्रिंटया फेस रिऑग्रिशन का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती।
- UPI Lite for wearable smart glasses enables small-value, hands-free payments via voice command and QR code scanning.
- स्मार्ट ग्लास के लिए यूपीआई लाइट छोटेमूल-्य वाले हाथ देन की सुविधा देता-मुक्त लेन- है, जिसमें वॉयस कमांड और क्यूआर कोड स्कैनिंग शामिल है।
- Aadhaar-based Face Authentication now allows setting or resetting UPI PINs quickly and inclusively, especially for first-time users and senior citizens.
- आधाररीसेट करने की प्रक्रिया को तेज़ /टआधारित फेस ऑथेंटिकेशन अब यूपीआई पिन से- और अधिक समावेशी बनाता है, विशेष रूप से नए उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
- Multi-Signatory UPI feature permits joint or multi-signatory accounts to approve payments through UPI smoothly.
- मल्टीसिग्रेचरी खातों को यूपीआई के -विधा से संयुक्त या मल्टीसिग्रेचरी यूपीआई सु- माध्यम से भुगतान को मंजूरी देने की सुविधा मिलती है।

**Ques: Which bank received a 'Letter of Caution' from RBI for non-compliance with KYC norms?**

**RBI ने KYC मानदंडों का पालन न करने पर किस बैंक को 'चेतावनी पत्र' जारी किया?**

- A. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D. Yes Bank / यस बैंक
- E. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued a 'Letter of Caution' to Axis Bank for non-compliance with Know Your Customer (KYC) norms.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने KYC (अपने ग्राहक को जानिएमानदंडों का पालन न करने ( ) पर एक्सिस बैंक Axis Bank) को 'चेतावनी पत्र' जारी किया है।
- The action came after RBI's review of Axis Bank's KYC compliance and internal systems.
- यह कार्रवाई RBI द्वारा Axis Bank की KYC अनुपालन और आंतरिक प्रणाली की समीक्षा के बाद की गई।
- Although the bank had taken corrective steps, RBI found it necessary to issue the caution to ensure strict adherence to its KYC instructions.
- बैंक द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद, RBI ने अपने KYC निर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी देना आवश्यक समझा।
- The letter advises Axis Bank to exercise greater caution and diligence to prevent recurrence of such issues.
- यह पत्र Axis Bank को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह देता है।
- KYC norms play a crucial role in preventing money laundering and fraud within the banking system.
- KYC नियम बैंकिंग प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

**Ques: The Government of India has allowed candidates from which sector to apply for top management roles in public sector banks including SBI?**

भारत सरकार ने किस क्षेत्र के उम्मीदवारों को एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है?

- A. Defence Sector / रक्षा क्षेत्र
- B. Education Sector / शिक्षा क्षेत्र
- C. Private Sector / निजी क्षेत्र
- D. Cooperative Sector / सहकारी क्षेत्र
- E. Agriculture Sector / कृषि क्षेत्र

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Government of India has opened top management positions in public sector banks (PSBs), including SBI, for private sector candidates.
- भारत सरकार ने एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए शीर्ष प्रबंधन पद खोले हैं।
- One of the four Managing Director positions in SBI is now available to candidates from the private sector or those working in public sector financial institutions.
- एसबीआई में प्रबंध निदेशक के चार पदों में से एक पद निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए खोला गया है।
- This reform aims to enhance transparency, competition, and merit-based hiring in top PSB roles.
- यह सुधार पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और योग्यताआधारित भर्ती को बढ़ावा देने का उद्देश्य - रखता है।

---

**Ques: Which bank launched the 'My Business QR' initiative to provide small merchants with digital profiles and mini online stores?**

किस बैंक ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्रोफाइल और मिनी ऑनलाइन स्टोर प्रदान करने के लिए 'My Business QR' पहल शुरू की है?

- A. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

- B. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D. State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- E. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- HDFC Bank launched the 'My Business QR' initiative, developed by the startup Vyaparify, to help small merchants create simple, scalable digital identities.
- एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप Vyaparify के सहयोग से 'My Business QR' पहल शुरू की, ताकि छोटे व्यापारियों को सरल और स्केलेबल डिजिटल पहचान बनाने में मदद मिल सके।
- When customers scan the QR, they can not only make payments but also view the shop's digital profile including name, address, phone number, and products.
- ग्राहक जब QR स्कैन करते हैं, तो वे केवल भुगतान नहीं कर सकते, बल्कि दुकान की डिजिटल प्रोफाइल जैसे नाम, पता, फोन नंबर और उत्पाद भी देख सकते हैं।
- The shop profile also functions as a mini online store where customers can browse products, place orders, and make payments online.
- यह डिजिटल प्रोफाइल मिनी ऑनलाइन स्टोर के रूप में भी काम करती है, जहाँ ग्राहक उत्पाद देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
- The initiative is part of HDFC Bank's 'Pitch for Business' program, supporting startups and innovators in presenting fintech solutions.
- यह पहल एचडीएफसी बैंक के 'Pitch for Business' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों को फिनटेक समाधान प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करता है।

**About HDFC Bank :**

- Established : August 1994
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Sashidhar Jagdishan
- Tagline : We Understand Your World

**Ques: How much loan amount has SBI provided to MSMEs through the SME Digital Business Loans platform in the last 15 months?**

प्रश्न एसबीआई ने पिछले :15 महीनों में SME डिजिटल बिजनेस लोन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई को कितनी राशि के ऋण प्रदान किए हैं?

- A. ₹54,000 crore
- B. ₹60,200 crore
- C. ₹74,434 crore
- D. ₹82,000 crore
- E. ₹90,000 crore

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The State Bank of India (SBI) provided loans worth ₹74,434 crore to 2.25 lakh MSMEs via its SME Digital Business Loans platform in the last 15 months.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पिछले 15 महीनों में अपनी SME डिजिटल बिजनेस लोन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.25 लाख एमएसएमई को ₹74,434 करोड़ के ऋण प्रदान किए।
- The loans were sanctioned in less than one hour, highlighting SBI's focus on quick digital lending.
- ऋण को एक घंटे से कम समय में मंजूर किया गया, जो एसबीआई की डिजिटल लेंडिंग और त्वरित वितरण पर फोकस को दर्शाता है।
- Launched in June 2024, the platform allows MSME entrepreneurs to apply online for loans up to ₹5 crore.
- जून 2024 में लॉन्च किए गए इस प्लेटफॉर्म से एमएसएमई उद्यमी ₹5 करोड़ तक के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

---

**Ques: RBI will consolidate how many circulars into 238 Master Directions by October 2025?**

**RBI अक्टूबर 2025 तक कितने परिपत्रों को 238 मास्टर डायरेक्शंस में समाहित करेगा?**

- A. 5,000
- B. 7,500
- C. 9,000
- D. 10,000

E. 3,500

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) will consolidate around 9,000 regulatory circulars issued by the Department of Regulation into 238 Master Directions.
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विनियमन विभाग द्वारा जारी लगभग 9,000 परिपत्रों को 238 मास्टर डायरेक्शंस में समाहित करेगा।
  - These Master Directions will cover 11 types of regulated entities and 30 functional areas, simplifying the regulatory framework.
  - ये मास्टर डायरेक्शंस 11 प्रकार के नियामित संस्थानों और 30 कार्य क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिससे नियामक ढांचा सरल बनेगा।
  - The move aims to reduce compliance burden, enhance clarity, and improve accessibility of rules for regulated entities.
  - इस कदम का उद्देश्य अनुपालन बोझ घटाना, स्पष्टता बढ़ाना, और नियामित संस्थानों के लिए नियमों की पहुंच बेहतर बनाना है।
  - RBI has also invited public feedback on these drafts till November 10, 2025.
  - RBI ने इन ड्राफ्ट्स पर सार्वजनिक सुझाव 10 नवंबर 2025 तक मांगे हैं।
- 

**Ques: Who has been appointed as the Executive Director of the Reserve Bank of India (RBI)?**

**किसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है?**

- A. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- B. Urjit Patel / उर्जित पटेल
- C. Viral Acharya / विरल अचार्य
- D. Raghuram Rajan / रघुराम राजन
- E. Sanjay Kumar Hansda / संजय कुमार हंसदा

**Answer: Option E**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- Sanjay Kumar Hansda has been appointed as the Executive Director (ED) of the Reserve Bank of India (RBI).
- संजय कुमार हंसदा को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है।
- His appointment follows the completion of his deputation as Senior Adviser to ED (India) at the International Monetary Fund (IMF).
- उनकी नियुक्ति उनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में ED (India) के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ड्यूटी पूरी करने के बाद हुई है।
- As ED, Sanjay Hansda will oversee the Department of Economic and Policy Research (DEPR) of RBI.
- ED के रूप में, संजय हंसदा RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) का संचालन करेंगे।

---

**Ques: As per the RBI's new rule, for how long can exporters keep their foreign exchange proceeds in a Foreign Currency Account at IFSC?**  
**RBI के नए नियम के अनुसार, निर्यातक अपने विदेशी मुद्रा आय को IFSC में विदेशी मुद्रा खाते में कितने समय तक रख सकते हैं?**

- A. 1 month
- B. 2 months
- C. 3 months
- D. 6 months
- E. 12 months

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed exporters to retain their foreign exchange proceeds in a Foreign Currency Account (FCA) at an International Financial Services Centre (IFSC) for up to 3 months.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में विदेशी मुद्रा खाते (FCA) में अपनी फॉरेक्स प्राप्तियों को 3 महीने तक रखने की अनुमति दी है।
- For accounts opened in any other jurisdiction, the time limit remains one month.

- अन्य किसी भी क्षेत्राधिकार में खोले गए खातों के लिए समय सीमा एक महीना ही रहेगी।
- This change was made by amending the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015.
- यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) विनियम, 2015 में संशोधन करके किया गया है।
- The move aims to provide greater flexibility to exporters, especially those in high-value industries such as gems and jewellery.
- यह कदम निर्यातकों, विशेष रूप से रत्न और आभूषण जैसे उच्चमूल्य क्षेत्रों को अधिक - लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- Experts believe this will help reduce conversion costs, improve hedging, and minimize currency volatility risks.
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह संशोधन मुद्रा परिवर्तन लागत को कम, हेजिंग में सुधार, और मुद्रा उतारचढ़ाव के जोखिमों को घटाने में मदद करेगा।-

---

**Ques: Which initiative has RBI launched to expand public awareness through WhatsApp?**

**आरबीआई ने WhatsApp के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौनशुरू सी पहल-की है?**

- A. RBI Digital Banking App / आरबीआई डिजिटल बैंकिंग ऐप
- B. RBI Kehta Hai verified WhatsApp channel / 'RBI कहता है' सत्यापित WhatsApp चैनल
- C. RBI SMS Alerts only / केवल आरबीआई एसएमएस अलर्ट
- D. RBI YouTube Awareness Campaign / आरबीआई यूट्यूब जागरूकता अभियान
- E. RBI Email Newsletter / आरबीआई ईमेल न्यूज़लेटर

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has been running the 'RBI Kehta Hai' campaign across print, TV, radio, digital platforms, and SMS to spread public awareness.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 'RBI कहता है' अभियान के माध्यम से प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और SMS पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है।

- In April 2025, RBI launched its verified WhatsApp channel to share official updates and awareness messages with citizens.
- अप्रैल 2025 में, RBI ने नागरिकों तक आधिकारिक अपडेट और जागरूकता संदेश पहुंचाने के लिए अपना सत्यापित WhatsApp चैनल लॉन्च किया।
- Citizens can now receive official messages from RBI via verified WhatsApp accounts — 99309 91935 (new) and 99990 41935 (existing).
- अब नागरिक सत्यापित WhatsApp अकाउंट्स — 99309 91935 (नया और (99990 41935 (पहले से उपयोग में के माध्यम से (RBI से आधिकारिक संदेश प्राप्त कर सकते हैं।

---

**Ques: Which organizations have launched the pilot for AI-driven UPI payments on ChatGPT in India?**

**भारत में ChatGPT पर AI-ड्रिवन UPI पेमेंट्स के लिए पायलट किसने शुरू किया है?**

- A. RBI / आरबीआई
- B. NPCI and Razorpay / NPCI और Razorpay
- C. Paytm / पेटीएम
- D. SBI / एसबीआई
- E. Google Pay / गूगल पे

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The National Payments Corporation of India (NPCI) and Razorpay, in collaboration with Microsoft-backed OpenAI, have launched a pilot for AI-driven e-commerce payments using ChatGPT.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और Razorpay ने Microsoft समर्थित OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT पर AI-आधारित ईकॉमर्स भुगतान के लिए एक - पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
- The pilot allows users to make UPI-based payments and shop online directly through ChatGPT.
- यह पायलट यूज़र्स को ChatGPT के माध्यम से सीधे UPI पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा देता है।
- BigBasket is one of the first merchants onboarded, while Axis Bank and Airtel Payments Bank are banking partners.

- BigBasket पहला मर्चेट पार्टनर है, जबकि Axis Bank और Airtel Payments Bank बैंकिंग पार्टनर हैं।
- The initiative showcases how AI agents can securely complete user-controlled transactions using biometric and PIN-based authentication.
- यह पहल दिखाती है कि AI एजेंट्स बायोमेट्रिक और PIN सत्यापन के माध्यम से सुरक्षित और यूज़रते हैं। नियंत्रित भुगतान कर सक-

---

**Ques: What is the target percentage of female workforce SBI aims to achieve by 2030?**

**एसबीआई का 2030 तक महिला कार्यबल का लक्ष्य कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है?**

- A. 25%
- B. 27%
- C. 30%
- D. 33%
- E. 35%

**Answer: C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The State Bank of India (SBI) has set a target to increase its female workforce to 30% by 2030 as part of its gender diversity initiative.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी लैंगिक विविधता पहल के तहत 2030 तक महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
- Currently, women constitute 27% of SBI's total workforce, with around 33% representation in frontline roles.
- वर्तमान में एसबीआई के कुल कर्मचारियों में 27% महिलाएं हैं, जबकि फ्रंटलाइन पदों पर यह संख्या लगभग 33% है।
- The initiative aims to promote inclusivity, gender balance, and equal opportunities across all levels of the organization.
- यह पहल संगठन में समावेशिता, लैंगिक संतुलन और सभी स्तरों पर समान अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

**Ques: Jio Payments Bank has won the MLFF project to implement FASTag-based ANPR system between which two cities?**

**जियो पेमेंट्स बैंक को FASTag आधारित ANPR सिस्टम लागू करने का MLFF प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच मिला है?**

- A. Delhi and Agra / दिल्ली और आगरा
- B. Mumbai and Pune / मुंबई और पुणे
- C. Gurugram and Jaipur / गुरुग्राम और जयपुर
- D. Bengaluru and Mysuru / बेंगलुरु और मैसूरु
- E. Hyderabad and Vijayawada / हैदराबाद और विजयवाड़ा

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- Jio Payments Bank, a subsidiary of Jio Financial Services, has secured a contract to implement the FASTag-based Automatic Number Plate Recognition (ANPR) system under the Multi-Lane Free Flow (MLFF) toll collection project.
- जियो पेमेंट्स बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी, को FASTag आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली लागू करने का MLFF टोल कलेक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
- The MLFF system will be operational at two toll plazas between Gurugram and Jaipur, enabling automatic toll deduction from FASTag-linked accounts without physical toll booths.
- यह MLFF प्रणाली गुरुग्राम और जयपुर के बीच दो टोल प्लाज़ा पर लागू होगी, जो FASTag से जुड़े खातों से स्वतः टोल राशि काटने की सुविधा प्रदान करेगी और भौतिक टोल बूथों की आवश्यकता को समाप्त करेगी।

---

**Ques: What are the key changes introduced in the Reserve Bank of India's bank locker rules for 2025?**

**भारतीय रिज़र्व बैंक के 2025 के बैंक लॉकर नियमों में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?**

- A. Mandatory revised agreement and digital copy for customers / ग्राहकों के लिए अनिवार्य संशोधित अनुबंध और डिजिटल कॉपी
- B. Biometric access, 24x7 CCTV, and alerts on locker access / बायोमेट्रिक एक्सेस,

24x7 CCTV, और लॉकर खोलने पर सूचनाएँ

C. Compensation up to 100 times annual rent if the bank is at fault / बैंक की गलती पर वार्षिक किराए का 100 गुना मुआवजा

D. Updated indicative annual rent based on locker size and city / लॉकर के आकार और शहर के अनुसार अद्यतन वार्षिक किराया

E. All of the above / ऊपर के सभी

**Answer: Option E**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- RBI is introducing new bank locker rules in 2025 that are designed to be safe, transparent, and customer-friendly.
- RBI 2025 में ऐसे नए बैंक लॉकर नियम लागू कर रहा है जो सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहकअनुकूल होंगे।-

**Key changes in Bank Locker Rules 2025 / 2025 के बैंक लॉकर नियमों में प्रमुख बदलाव:**

**Locker Agreement / लॉकर अनुबंध**

- Mandatory revised agreement for all users.
- Banks will provide a copy of the agreement physically or digitally.
- Agreement will clearly detail the rights and obligations of both parties.
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य संशोधित अनुबंध।
- बैंक अनुबंध की प्रति भौतिक या डिजिटल रूप में प्रदान करेंगे।
- अनुबंध में दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।

**Security Measures / सुरक्षा उपाय**

- Biometric access, 24x7 CCTV, and alerts whenever the locker is opened.
- CCTV footage will be stored for at least 180 days.
- Customers will get instant SMS/email notifications on locker access.
- बायोमेट्रिक एक्सेस, 24x7 CCTV, और लॉकर खोलने पर सूचनाएँ।
- CCTV फुटेज कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रहेगा।
- लॉकर खोलने पर ग्राहकों को तुरंत SMS/email द्वारा सूचित किया जाएगा।

### Compensation for Loss / नुकसान के लिए मुआवजा

- Bank will pay up to 100 times the annual rent if found at fault.
- बैंक की गलती होने पर वार्षिक किराए का 100 गुना मुआवजा।

### Annual Rent / वार्षिक किराया

- Updated indicative rent ranges from ₹2,000 to ₹10,000 depending on locker size and city.
- लॉकर के आकार और शहर के अनुसार ₹2,000 – ₹10,000 वार्षिक किराया।

### Prohibited Items / प्रतिबंधित वस्तुएँ

- Customers can store jewelry, property papers, insurance policies, and confidential documents.
- Cash, arms, explosives, or hazardous items are strictly prohibited.
- ग्राहक आभूषण, संपत्ति दस्तावेज़, बीमा पॉलिसी और गोपनीय दस्तावेज़ रख सकते हैं।
- नकद, हथियार, विस्फोटक और हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध।

---

**Ques: According to CBDT data, India's net direct tax collection grew by what percentage to ₹11.89 lakh crore during April–October 2025?**

**CBDT के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ हुआ?**

- A. 4.8%
- B. 5.5%
- C. 6.3%
- D. 7.2%
- E. 8.1%

**Answer: Option C**

---

### Explanation / व्याख्या:

- As per CBDT, India's net direct tax collection rose 6.33% to ₹11.89 lakh crore in April–October 2025, driven by strong non-corporate tax receipts and a drop

in refunds.

- CDBT के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.33% बढ़कर ₹11.89 लाख करोड़ हुआ, जो गैरकारपोरेट कर संग्रह में वृद्धि और रिफंड में कमी के कारण - संभव हुआ।
- Non-corporate taxpayers (individuals, HUFs, firms, associations, local authorities, artificial juridical persons) contributed ₹6.56 lakh crore, while corporate tax collection stood at ₹5.02 lakh crore.
- गैरव्यक्ति) कारपोरेट करदाताओं-, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, संघ, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का योगदान (₹6.56 लाख करोड़ रहा, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह ₹5.02 लाख करोड़ रहा।
- Refund issuances dropped by 16% to ₹2.03 lakh crore, helping boost net collections.
- रिफंड जारी करने में 16% की गिरावट रही और यह ₹2.03 लाख करोड़ रहा, जिससे शुद्ध संग्रह में वृद्धि हुई।

---

**Ques: Which city has launched India's first QR code-based kiosk for traffic challan payments?**

**भारत का पहला QR कोडआधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क किस शहर में लॉन्च - किया गया है?**

- A. Mumbai / मुंबई
- B. Gurugram / गुरुग्राम
- C. Bengaluru / बेंगलुरु
- D. Hyderabad / हैदराबाद
- E. Pune / पुणे

**Answer: B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- Gurugram has become the first city in India to introduce a QR code-based digital kiosk for paying traffic challans.
- गुरुग्राम देश का पहला शहर बन गया है जिसने QR कोडआधारित डिजिटल कियोस्क के - माध्यम से ट्रैफिक चालान भुगतान की सुविधा शुरू की है।
- The kiosk was developed jointly by Gurugram Police and the Gurugram

Metropolitan Development Authority (GMDA) to make challan payments faster, simpler, and cashless.

- इस कियोस्क को गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने मिलकर विकसित किया है, ताकि चालान भुगतान तेज़, सरल और कैशलेस हो सके।
- The project is part of a Corporate Social Responsibility (CSR) initiative and is expected to be expanded to more high-footfall locations across the city to promote digital governance and public convenience.
- यह परियोजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल का हिस्सा है और इसे नागरिक सुविधा और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए शहर के अन्य व्यस्त क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है।

---

**Ques: The Government of India has revised guidelines to allow candidates from which sector to apply for top leadership roles like Managing Director (MD) in SBI and Executive Director (ED) in Public Sector Banks (PSBs)?**

भारत सरकार ने किस क्षेत्र के उम्मीदवारों को SBI में प्रबंध निदेशक (MD) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में कार्यकारी निदेशक (ED) जैसे शीर्ष पदों के लिए आवेदन की अनुमति देने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया है-?

- A. Defence Sector / रक्षा क्षेत्र
- B. Private Sector / निजी क्षेत्र
- C. Cooperative Sector / सहकारी क्षेत्र
- D. Public Enterprises / सार्वजनिक उपक्रम
- E. Non-Banking Financial Companies (NBFC) Sector / गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र-

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The government has revised the rules so that key senior leadership positions in Public Sector Banks (PSBs)—such as Managing Director (MD) roles in SBI and Executive Director (ED) roles across PSBs—are now open to private sector (external) candidates.
- सरकार ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में वरिष्ठ नेतृत्व पद — जैसे SBI में प्रबंध निदेशक (MD) और अन्य PSBs में कार्यकारी निदेशक (ED) — निजी क्षेत्र (बाहरी उम्मीदवारों) के लिए भी खुले होंगे।

- Earlier, these top posts were typically filled by officers already working within PSBs. Under the new rules, at least one MD post in SBI (out of multiple MD positions) will be open to external applicants.
- पहले ये शीर्ष पद केवल PSB के आंतरिक अधिकारियों द्वारा ही भरे जाते थे। नए नियमों के तहत, SBI के कई MD पदों में से कमकम एक पद-से- अब बाहरी उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा।
- Officers from PSBs at General Manager (GM) or Chief General Manager (CGM) level may also qualify under specific conditions.
- PSB के महाप्रबंधक (GM) या मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर के अधिकारी भी कुछ शर्तों के तहत पात्र होंगे।
- Candidates serving as Chief Vigilance Officers (CVOs) are not eligible for these top positions.
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में कार्यरत उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) will conduct the selection process, including behavioural and competency assessments.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) चयन प्रक्रिया संचालित करेगा, जिसमें व्यवहारिक और क्षमता मूल्यांकन शामिल होगा।

#### **Eligibility for private sector candidates / निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए पात्रता:**

- SBI MD : 21 years total experience (including 15 years in banking) / कुल 21 वर्ष का अनुभव जिसमें 15 वर्ष बैंकिंग में (. Must have served either 2 years at Board level or 3 years at one level below Board / बोर्ड स्तर पर 2 वर्ष या बोर्ड से नीचे एक स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक
- ED in Nationalised Banks : 18 years total experience (including 12 years in banking) / कुल 18 वर्ष का अनुभव जिसमें 12 वर्ष बैंकिंग में (. Must have served 3 years at the highest level below Board / बोर्ड से नीचे उच्चतम स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक

---

**Ques: What was India's retail inflation rate in September 2025 — the lowest in 8 years?**

**सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर, जो 8 साल में सबसे कम रही, कितनी थी?**

- A. 2.6%
- B. 1.8%
- C. 1.54%
- D. 1.46%
- E. 3.1%

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- India's retail inflation (CPI) fell sharply to 1.54% in September 2025, the lowest since June 2017, due to a decline in food and fuel prices.
- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर 1.54% पर आ गई, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है, इसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी रहा।
- Core inflation, excluding food and fuel, inched up slightly to 4.43% due to rising precious metal prices.
- कोर मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर (भोजन और ईंधन को छोड़कर) 4.43% पर पहुंच गई, कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण।
- The Consumer Food Price Index (CFPI) remained at -2.28%, reflecting cheaper food items.
- खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) -2.28% पर रहा, जो भोजन की वस्तुओं के सस्ते होने को दर्शाता है।
- The rate is below RBI's lower tolerance band of 2%, signaling potential for monetary easing in December.
- यह दर RBI के 2% के निचले सहनशीलता बैंड से नीचे है, जिससे दिसंबर में मौद्रिक राहत की संभावना बढ़ गई है।

---

**Ques: Which institution launched four new digital payment initiatives — including IoT-based UPI Payments and UPI Reserve Pay — at the Global Fintech Fest 2025?**

**किस संस्था ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में IoT-आधारित UPI भुगतान और UPI रिजर्व पे सहित चार नई डिजिटल भुगतान पहल शुरू कीं?**

- A. National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- B. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

- C. State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E. NITI Aayog / नीति आयोग

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) launched four digital payment initiatives aimed at improving customer convenience and innovation in the fintech ecosystem during the Global Fintech Fest 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में ग्राहक सुविधा और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चार नई डिजिटल भुगतान पहलें शुरू कीं।

**Here are the four initiatives / चार प्रमुख पहलें:**

**IoT-based UPI Payments / IoT-आधारित UPI भुगतान**

- Enables UPI transactions through connected smart devices (like smart cars, TVs, or wearables).
- स्मार्ट कार, टीवी, या वियरेबल जैसे स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से स्वचालित रूप से UPI लेनदेन की सुविधा देता है।

**Banking Connect (Interoperable Net Banking) / बैंकिंग कनेक्ट संचालनीय -अंतर)  
(नेट बैंकिंग)**

- Provides a single interface for merchants and payment aggregators to connect with multiple banks — eliminating the need for multiple integrations.
- व्यापारियों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म से कई बैंकों से जुड़ने की सुविधा देता है, जिससे बारबार इंटीग्रेशन की आवश्यकता समाप्त होती है।-

**UPI Reserve Pay / UPI रिज़र्व पे**

- Allows users to reserve a part of their credit card or pre-approved credit line for UPI payments, simplifying repeat transactions.
- उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट कार्ड या पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन का एक हिस्सा-UPI भुगतान के लिए आरक्षित करने की सुविधा देता है।

### AI-based UPI HELP / एआई आधारित-UPI हेल्प

- An AI-powered helper (developed using NPCI's small language model) that assists users with payments, mandates, dispute resolution, and status tracking.
- NPCI के स्मॉल लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित एआई सहायक जो भुगतान, मैंडेट, विवाद निवारण और स्थिति जांच में उपयोगकर्ताओं की सहायता करता है।

**Ques: What is the Flipkart Bharat Yatra Card, and which payment network powers it?**

**फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड क्या है, और इसे किस भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है?**

- A. A credit card powered by Visa / वीज़ा द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड
- B. A debit card powered by Mastercard / मास्टरकार्ड द्वारा संचालित डेबिट कार्ड
- C. A prepaid transit card powered by RuPay / रूपे पे संचालित प्रीपेड ट्रांज़िट कार्ड
- D. A loyalty card powered by American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संचालित लॉयल्टी कार्ड
- E. A gift card powered by UPI / यूपीआई द्वारा संचालित गिफ्ट कार्ड

**Answer: Option C**

**Explanation / व्याख्या:**

- The Flipkart Bharat Yatra Card is a prepaid transit card that enables seamless cashless travel across metros, buses, and other public transport networks supporting the National Common Mobility Card (NCMC) standard.
- फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड एक प्रीपेड ट्रांज़िट कार्ड है जो मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बिना नकद भुगतान के यात्रा की सुविधा प्रदान करता है और यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) मानक का समर्थन करता है।
- It is powered by the RuPay payment network and is available in cities including New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, and Ahmedabad.
- यह रूपे भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित है और नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में उपलब्ध है।
- The card can be used for offline transactions up to a balance of ₹2,000.
- इस कार्ड का उपयोग ऑफ़लाइन लेन-देन के लिए ₹2,000 तक के बैलेंस तक किया जा

सकता है।

---

**Ques: What is the main purpose of RBI's Digital Payments Intelligence Platform (DPIP)?**

**आरबीआई के डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

- A. Boost UPI transaction limits / यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाना
- B. Detect and prevent payment frauds in real time / भुगतान धोखाधड़ी की रियल-टाइम पहचान और रोकथाम
- C. Promote credit card usage / क्रेडिट कार्ड उपयोग को बढ़ावा देना
- D. Enable offline digital payments / ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना
- E. Create a digital rupee monitoring system / डिजिटल रुपये की निगरानी प्रणाली बनाना

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The Digital Payments Intelligence Platform (DPIP) is an AI-driven initiative by RBI aimed at detecting and preventing payment frauds in real time.
- डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) भारतीय रिज़र्व बैंक की एआईआधारित - पहल है, जिसका उद्देश्य भुगतान धोखाधड़ी की रियलटाइम पहचान और रोकथाम करना - है।
- Phase 1 involves a negative registry integrating data from banks, telecom operators, and the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C).
- पहले चरण में नेगेटिव रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसमें बैंकों, टेलीकॉम ऑपरेटरों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का डेटा जोड़ा गया है।
- Phase 2 will enable real-time sharing of fraud-related data among banks to allow preventive actions like verification or temporary debit freezes.
- दूसरे चरण में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित डेटा रियलटाइम में साझा करेंगे-, ताकि पूर्व-निवारक कार्रवाई जैसे सत्यापन या अस्थायी डेबिट फ्रीज की जा सके।
- AI-based models alert banks instantly about potential fraud transactions, enhancing payment security.
- एआई मॉडल संभावित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में तुरंत बैंकों को अलर्ट करेंगे, जिससे भुगतान सुरक्षा बढ़ेगी।

**Ques: Which bank signed an MoU with the BSF under the Rakshak Salary Package to enhance financial benefits for personnel and veterans?**

**कौन सा बैंक BSF के साथ रक्षक सैलरी पैकेज के तहत कर्मियों और वेटरन्स के लिए वित्तीय लाभ बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किया?**

- A. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B. Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया
- C. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D. Canara Bank / केनरा बैंक
- E. HDFC Bank / HDFC बैंक

**Answer: Option B**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- Bank of India signed a Memorandum of Understanding with the Border Security Force (BSF) under the Rakshak Salary Package to provide enhanced financial benefits to BSF personnel and veterans.
- बैंक ऑफ इंडिया ने BSF कर्मियों और वेटरन्स को बेहतर वित्तीय लाभ देने के लिए रक्षक सैलरी पैकेज के तहत सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Enhanced Personal Accident Insurance: Complimentary coverage up to ₹1 crore
- व्यक्तिगतरूप से दुर्घटना बीमा बढ़ाया : ₹1 करोड़ तक निशुल्क कवरेज:
- Air Accident Coverage: Coverage up to ₹2 crore
- हवाई दुर्घटना कवरेज : ₹2 करोड़ तक कवरेज

**About Bank of India :**

- Established : 7 September 1906
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Rajneesh Karnatak
- Tagline : Relationship beyond Banking

**Ques: Which company has partnered with NPCI to launch India's first wearable payments ecosystem?**

**भारत का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए NPCI ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?**

- A. PhonePe / फोनपे
- B. Paytm / पेटीएम
- C. Muse Wearables / म्यूज़ वेयरेबल्स
- D. Pine Labs / पाइन लैब्स
- E. Razorpay / रेज़रपे

**Answer: Option C**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- Muse Wearables, an IIT-Madras-incubated startup, has partnered with NPCI to launch India's first wearable payments ecosystem using smart rings called "Ring One."
- IIT-मद्रास से शुरू हुआ स्टार्टअप Muse Wearables ने NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें "Ring One" स्मार्ट रिंग का उपयोग किया जाता है।
- The ecosystem uses Muse Wallet and the RuPay network, enabling secure, contactless payments without a phone, card, or wallet.
- यह प्रणाली Muse Wallet और RuPay नेटवर्क पर आधारित है, जिससे उपयोगकर्ता बिना फोन, कार्ड या वॉलेट के सुरक्षित और कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं।
- Muse Wallet also serves as India's first secure element tokenisation platform, converting card details into secure digital tokens for safer transactions.
- Muse Wallet भारत का पहला सुरक्षित टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है, जो कार्ड की जानकारी को डिजिटल टोकन में बदलकर भुगतान को और सुरक्षित बनाता है।

---

**Ques: What are the key changes introduced by RBI in 2025 regarding CIBIL scores for bank customers?**

**2025 में बैंक ग्राहकों के लिए CIBIL स्कोर के संबंध में RBI द्वारा कौनकौन से प्रमुख बदलाव - किए गए हैं?**

- A. CIBIL scores will now be updated twice a month / CIBIL स्कोर अब महीने में दो

बार अपडेट होंगे

B. Customers will be informed whenever their score is checked / जब भी ग्राहक का स्कोर देखा जाएगा, उन्हें सूचित किया जाएगा

C. Banks cannot reject requests secretly; reasons must be communicated / बैंक गुप्त रूप से अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकते; कारण बताना अनिवार्य है

D. Customers get one free full credit report per year / ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी

E. All of the above / ऊपर के सभी

**Answer: Options E**

---

**Explanation / व्याख्या:**

• RBI has introduced six rules to improve transparency and customer benefits related to CIBIL scores:

• RBI ने CIBIL स्कोर से संबंधित पारदर्शिता और ग्राहक लाभ बढ़ाने के लिए छह नियम लागू किए हैं:

- **Faster updates:** CIBIL scores will now be updated every 15 days.

तेज़ अपडेट: CIBIL स्कोर अब हर 15 दिन में अपडेट होंगे।

- **Customer notification:** Customers must be informed whenever their score is checked.

ग्राहक को सूचना: जब भी बैंक ग्राहक का स्कोर देखे, ग्राहक को सूचित करना अनिवार्य है।

- **No secret rejections:** Banks cannot reject requests secretly; reasons must be communicated.

गुप्त अस्वीकृति नहीं: बैंक गुप्त रूप से अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकते; कारण बताना अनिवार्य है।

- **Free annual report:** Credit companies must provide one free full credit report per year.

वार्षिक मुफ्त रिपोर्ट: क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में प्रदान करनी होगी।

- **Default notifications:** Customers must be informed if reported as defaulters.

डिफॉल्ट की सूचना: यदि ग्राहक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किया जाए, तो उन्हें सूचित करना अनिवार्य है।

- **Resolution timeline:** Issues must be resolved within 30 days; banks and

credit companies have defined timelines with penalties for delays.

- Once a bank informs a credit information company about an error, the company must address it within 9 days. Similarly, banks must resolve customer complaints within 21 days.
- If they fail to do so, the responsible party will face a penalty of ₹100 per day for the delay.

**समाधान की समय सीमा:** समस्याओं को 30 दिनों में हल करना अनिवार्य है; विलंब होने पर ₹100 प्रति दिन का जुर्माना लागू होगा।

जब कोई बैंक किसी क्रेडिट सूचना कंपनी को किसी त्रुटि की सूचना देता है, तो कंपनी को 9 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। इसी प्रकार, बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 21 दिनों के भीतर करना होगा।

यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष को प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना देना होगा।

---

**Ques: Under the new EPFO withdrawal rules, what percentage of the Provident Fund balance can members now withdraw?**

**EPFO के नए नियमों के तहत सदस्य अब अपने भविष्य निधि (PF) बैलेंस का कितना प्रतिशत निकाल सकते हैं?**

- A. 50%
- B. 75%
- C. 90%
- D. 100%
- E. 25%

**Answer: Option D**

---

**Explanation / व्याख्या:**

- The EPFO has approved liberalised withdrawal rules, merging 13 old provisions into a single streamlined framework, allowing members to withdraw up to 100% of their EPF balance.
- EPFO ने 13 पुराने प्रावधानों को मिलाकर सरल ढांचा बनाया है, जिससे सदस्य अब अपने EPF बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं।
- Withdrawals are categorised into Essential Needs (illness, education, marriage), Housing Needs, and Special Circumstances.

- निकासी को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है — मूलभूत आवश्यकताएँ (बीमारी), शिक्षा, विवाह, आवास संबंधी आवश्यकताएँ और विशेष परिस्थितियाँ।
- Minimum service requirement reduced to 12 months, and 25% of contributions will remain as a mandatory balance.
- न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह कर दी गई है, और 25% योगदान खाते में न्यूनतम शेष राशि के रूप में रखा जाएगा।
- No documentation or specific reason is required, simplifying access for over 7 crore subscribers.
- अब किसी दस्तावेज़ या कारण की आवश्यकता नहीं है, जिससे 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है।

